

## नव नगिमति फर्मों द्वारा राजनीतिक अंशदान

[स्रोत: द हट्टि](#)

तीन वर्ष से कम पुरानी कंपनियों को राजनीतिक अंशदान (Political Contribution) देने से रोकने वाले नियमों के बावजूद , हालिया आँकड़ों से भारत में नव नगिमति कंपनियों द्वारा [चुनावी बाँण्ड](#) की चौकाने वाली खरीद का पता चलता है ।

- **कंपनी अधिनियम, 2013** तीन वर्ष या उससे कम अवधि के अंतर्गत पंजीकृत हुई कंपनियों को राजनीतिक अंशदान देने से रोकता है, जिसका उद्देश्य [शेल कंपनियों](#) को राजनीतिक दलों में अंशदान देने से रोकना है ।
  - 2017 के संशोधन ने योगदान पर लगी सीमा को हटा दिया लेकिन **तीन वर्ष के नषिध** को बरकरार रखा ।
- **कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182** में उल्लंघन के लिये दंड की रूपरेखा दी गई है, जिसमें अधिकारियों के लिये **जुरमाना और कारावास** शामिल है ।



# Chronology of events in Electoral bonds case

Electoral bond scheme introduced in the Finance Bill

2017

2017  
Sep 14

NGO 'Association for Democratic Reforms', lead petitioner, moves SC challenging the scheme

SC issues notices to Centre and EC on PIL filed by the NGO

2017  
Oct 03

2018  
Jan 2

The Central government notifies electoral bond scheme.

Electoral bond scheme amended to increase sale days from 70 to 85 in a year where any assembly election may be scheduled

2022  
Nov 7

2023  
Oct 16

SC bench headed by CJI DY Chandrachud refers pleas against scheme to five-judge Constitution bench

Five-judge Constitution bench headed by CJI D Y Chandrachud commences hearing on pleas against scheme

2023  
Oct 31

2023  
Nov 2

SC reserves verdict

SC delivers unanimous judgement annulling the scheme, calling it 'unconstitutional'

2024  
Feb 15

//

और पढ़ें... [SC ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया](#)

